पर्यावरण कानूनों का पालन जरूरी : मनमोहन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश में पर्यावरण कानूनों का पालन होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि लाइसेंस राज वापस आ जाए। प्रधानमंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि प्रदूषण करने वाला उसकी कीमत चुकाए - के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन 2011का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल विकास की रणनीति तमाम आर्थिक फैसलों का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसका पालन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए होना चाहिए।

गौरतलब है कि मनमोहन सिंह का यह वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब पर्यावरण मंत्रालय पर एक तरफ विकास को रोकने के आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तमाम उल्लंघनों के बावजूद हरी झंडी देने का मामला सामने आ रहा है। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, डोमेनियन रिपब्लिक के राष्ट्रपति डॉ. लिओनेल फर्नांडीस और सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर मनमोहन सिंह को टेरी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप पुरस्कार भी दिया गया। मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सार्थक पहल करने और राष्ट्रीय एक्शन प्लान तैयार करने की

- इसका मतलब लाइसेंस राज वापसी नहीं
- विकास के साथ समझौता नहीं किया जा सकता

एवज में दिया गया। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में जयराम रमेश का पक्ष लेते हुए विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि नियंत्रण करने वाली नीतियों तथा ढांचे को सही ढंग से विकसित करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ कड़े मानक बनाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इन्हें लागू करना मुश्किल होता है। हालांकि यह कहते हुए उन्होंने दोहराया कि कानूनों के पालन का मतलब लाइसेंस राज की वापसी नहीं है, क्योंकि देश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने विस्तार से प्रदूषण नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन आदि पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि भारत ने प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई के लिए सख्त नियम बनाए हैं। मनमोहन ने बताया कि पिछले साल सरकार ने राष्ट्रीय साफ ऊर्जा फंड के लिए कोयले के घरेलू तथा आयात पर पांच फीसदी सेस (अधिभार) लगाया था। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि औद्योगिक देशों को यह स्पष्ट प्रतिबद्धता करनी चाहिए कि वे कोपेनहेगन सम्मेलन में तय लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत-चीन तथा बाकी विकासशील देशों द्वारा खुद ही लक्ष्य निर्धारित करने की तारीफ करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए माहौल बना।

इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि उनके देश में युद्ध सा माहौल है और लगातार अशांति चल रही है इसलिए पर्यावरण का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। छोटे देश सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स ए मिशेल ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा कि द्वीप देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से खतरा जीवन और मौत का खतरा है। वे समुद्र का पानी बढ़ने से विलुप्त हो जाएंगे इसलिए वे चाहते हैं कि विकसित देश कानूनी रूप से बाध्यकारी कदम उठाएं। तीन दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से आए लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खास पहल होने की उम्मीद नहीं है। इसके बजाय स्थानीय प्रयासों पर ही जोर देना चाहिए। इसके उलट संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े विज्ञानी प्रो.जेफरी डी.सेश ने कहा कि विकसित देशों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।